मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

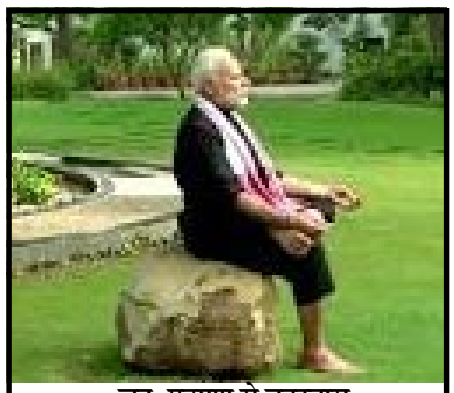

जन, प्रदूषण से बदहवास
महान जन- फिट है बॉस !

सेक्टर-22 'स्मार्ट'	3
मोदी से 48 सवाल	4
भ्रष्टाचार में डूबा भारत	5
रोगी जेल बीमार जेलर	8

वर्ष 31 अंक -25 फ़रीदाबाद 17-23 जून 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2

कृष्णपाल ने खोला राज, सूखी यमुना में चलेंगे जहाज

झूठ बोलने से मोदी के मंत्री को भी परहेज नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 4 साल की देरी से बनना शुरू हुआ मंझावली का यमुना पुल मंत्री जी के लिये अब फुल टाइम जॉब हो गया है। उन्हें नारियल फ़ोड़ने व झूठ बोलने के अलावा और तो कोई काम है नहीं लिहाजा अब आये दिन मंझावली के इसी निर्माणाधीन पुल के पास खड़े रहा करेंगे।

इसी श्रंखला में 12 जून को वे अपने पुत्र देवेन्द्र चौधरी व कुछ अन्य छुटभैये नेताओं और पत्रकारों को लेकर वहां पहुंच गये। पुत्र देवेन्द्र अभी राजनीति के गुर अपने पिता से सीख रहे हैं और फ़िलहाल नगर निगम के वरिष्ठ उपमहापौर भी हैं। इस अवसर पर मंत्री जी ने बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी कि इस यमुना नदी में जहाज चलाये जायेंगे। इसके लिये पुल के नीचे बन रहे पिलरों की ऊंचाई 3-3 मीटर बढाने व पिलर से पिलर के बीच के फ़ासले को 15-15 मीटर बढाने के लिये इसके डिज़ाइन में परिवर्तन कराया जा रहा है।

चलो, इस पुल के डिजाइन में तो परिवर्तन करके गूजर महोदय पुल की ऊंचाई को बढवा लेंगे। लेकिन दिल्ली के भीतर यमुना पर बने उन 7 पुलों का क्या होगा जिनकी ऊंचाई कम है? क्या गूजर महोदय उन सभी पुलों को भी तुड़वाकर अपने जहाज चलायेंगे? एक सवाल यह भी उठता है कि बीते चार

साल में तो गूजर महोदय ने कोई जहाज चलाया नहीं अब पुल बनने के बक्त जहाज चलाने की क्या सुझी? समझा जाता है कि निमार्णाधीन पुल के डिजाइन में परिवर्तन करने से लागत में करोड़ों की वृद्धि हो जायेगी जिससे निर्माता कम्पनी को अच्छा-खासा लाभ होगा। जाहिर है कि जब निर्माता को अधिक लाभ होगा तो वह लाभ कराने वालों को भी कुछ न कुछ अच्छा-खासा नजराना एवं चंदा दे पायेगा।

विदित है कि इस वक्त यमुना में एक बूंद पानी नहीं है। पिछले दिनों पानीपत क्षेत्र से आई एक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि किस तरह लोग अपने परिजनों की अस्थियों को यमुना के रेत में दबा रहे हैं जो बरसात के समय पानी आने पर बह जायेंगी। ऐसे में दिल्ली को पीने का पानी तक भी उपलब्ध होना असंभव हो रहा है। ऐसे में मंत्री कृष्णपाल जी यमुना में जहाज चलायेंगे।

वैसे मोदी के सच्चे भक्तों के लिये कुछ भी असंभव नहीं है; वे रात के 12 बजे सूरज भी दिखा सकते हैं तो दिन में तारे। ऐसे में कृष्णपाल के लिये सूखी यमुना में जहाज चलाना क्या मुश्किल काम है।

यद्यपि गूजर महोदय बार-बार ज़ोर देकर कह रहे हैं कि पुल का निर्माण 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा। परन्तु उनकी यह घोषणा गले से बिल्कुल नहीं उतरती। जब डीपीआर बनाने व अन्य काग़जी कार्यवाही करने में करीब चार साल लग गये तो वास्तविक पुल 6 माह में, वह भी यमुना नदी पर कैसे बन सकता है जबकि 2-4 सप्ताह बाद बरसातें शुरू हो जायेंगी और यमुना बहने लगेगी।

जानकार बताते हैं कि मंत्री जी इसके लिये काफ़ी पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं। इसी कड़ी में 17 जून को निर्माण स्थल पर एक भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। लगता है इससे 'भगवान' प्रसन्न होकर उनकी मुराद पूरी कर दे और पुल उनके द्वारा घोषित तिथि पर पूरा हो सके, वरना निर्माण करने वाले इन्जीनियरों व मज़दूरों के बस का तो यह काम दिखता नहीं।

51 करोड़ के शिलान्यास लेकर कृष्णपाल फ़िर निकले नारियल फ़ोड़ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) मोदी एवं भाजपा की रणनीति अनुसार जनता को भ्रमित करने के लिये पार्टी नेताओं को हर रोज़ कोई न कोई शगूफ़ा छोड़ते रहना चाहिये। इसी नीति के तहत स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने 11 जून को अपने गांव मेवला महाराजपुर तथा इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी में 51 करोड़ के कामों का शिलान्यास किया। इसमें गांव का सामुदायिक भवन, सड़कें, नाले व नालियां आदि तो हैं ही साथ में साढ़े 10 करोड़ का एक अस्पताल भी सेक्टर 45 में बनेगा जिसका काम 15 अगस्त को शुरू होगा (जैसा कि मंझावली वाले यमुना पुल का 4 वर्ष पूर्व हुआ था)। जो काम अगस्त में होना है तो उसका ढोल जून में क्यों पीट रहे हैं मंत्री जी?

अस्पताल की इमारत पर तो दसियों करोड़ खर्च करेंगे मगर उसमें इलाज करने वाले डॉक्टर व स्टाफ़ तथा आवश्यक सामान कभी नहीं आयेगा। ऐसा ही एक अस्पताल सेक्टर 55 में गत 5 वर्षों से बना खड़ा है जिसकी रखवाली के लिये एक चौकीदार का खर्चा अलग से सरकार उठा रही है। अभी 2-3 माह पूर्व मंत्री जी ने तिगांव पीएचसी (प्राइमरी हैल्थ सेंटर) का दर्जा बढा कर सीएचसी (कम्युनिटी हैल्थ सेंटर) बनाने के लिये नई इमारत का काम चालू कराया था। जबकि वहां पीएचसी के लिये भरी आवश्यक स्टाफ़ नहीं है। इसी तर्ज़ पर धड़ाधड़ कॉलेजों की इमारतों का निर्माण किया जा रहा है।

दरअसल सब ड्रामेबाज़ी सिर पर खड़े लोकसभा चुनावों को लेकर की जा रही है। इमारतों के निर्माण में जो सीधी लूट होती है उससे तो नेताओं का चुनाव खर्च निकलेगा और इमारतें बनती देख जनता को विकास का भ्रम होना स्वाभाविक है। इसके विपरीत यदि मौजूदा इमारतों में ही पर्याप्त स्टाफ़ और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा दें तो उससे न तो विकास कार्यों की गिनती बढती है न लूट की आमदनी।

इसी दौरान गूजर ने मेवला के रेलवे अंडरपास का भी उल्लेख करते हुये इस पर साढे 19 करोड़ खर्च किये जाने की बात कही। विदित है कि यह अंडरपास गत चार वर्षों से निर्माणाधीन है। इसमें सबसे कठिन काम होता है चलती रेलवे लाइनों के नीचे लेंटर डालने का जो रेलवे के इन्जीनियरों ने करीब एक वर्ष पहले डाल कर निपटा दिया था। रही बात दोनों ओर के रैंम्प बनाने का वह काम हरियाणा सरकार के चोरों के जिम्मे है। इन चोरों की कार्यवाही को पूरे शहर ने ओल्ड फ़रीदाबाद वाले अंडर पास बनाने के वक्त देखा था। इसे बनाने में 6 वर्ष से ज़्यादा तो लगाये सो लगाये साथ में हर वर्ष इसका बजट भी बढाते गये जो सीधी लूट थी। वही प्रोग्राम अब यहां मेवला अंडरपास के नाम पर चल रहा है।

नीरव मोदी को मोदी सरकार ने जानबूझकर भगाया है !

मजदूर मोर्चा, विशेष

इंटरपोल बता रहा है कि भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट रद्द किए जाने के बावजूद तीन देशों की चार बार यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर कर चुका है।

हमारा विदेश मंत्रालय बता रहा था कि नीरव मोदी का पासपोर्ट 24 फरवरी को रद्द किया था ओर इंटरपोल कह रहा है कि नीरव मोदी ने ये यात्राएं मार्च महीने में की हैं।

5 जून को भारतीय एजेंसियों को लिखे खत में इंटरपोल ने कहा है कि नीरव मोदी 15 मार्च से 31 मार्च के बीच भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग की यात्राएं की, उसने इस पासपोर्ट पर चार बार- 15 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को यात्राएं की।

अगर आपने पासपोर्ट रद्द कर दिया तो इसकी सूचना आपने तुंरन्त दूसरे देशों को क्यों नही दी ? और वो भी अमेरिका ब्रिटेन हांगकांग जैसे देशो को जिन्हें सबसे पहले सूचना देना चाहिए थी, मतलब साफ है कि इसके पीछे गहरा षडयंत्र है, और नीरव मोदी को मामला सेटल करने के लिए टाइम दिया जा रहा है।

केजीपी का यमराज बने नितिन गडकरी!

फ़रीदाबाद (म.मो.)। हरियाणा के डीजीपी बलजीत संधू के केजीपी एक्सप्रेस वे पर गति सीमा घटाने के अनुरोध को केन्द्रीय सड़क मंत्रालय के सर्वेसर्वा नितिन गडकरी ने ठुकरा दिया है। उधर बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किये, यातायात के लिए खोले गए इस राजमार्ग पर भारी टोल उगाही 15 जून से शुरू कर दी गयी है।

इस 27 मई को प्रधानमन्त्री मोदी ने कैराना उपचुनाव के चलते आनन-फानन में केजीपी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन एक ताम-झाम भरे बहुप्रचारित रोड शो से किया था। तब से इस पर दुर्घटनाओं और मौतों का अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल, इस 'विकास' के नरक में यमराज की भूमिका स्वयं सड़क पुरुष नितिन गडकरी ने संभाल रखी है।

भारत में सड़क यातायात का कोई भी विशेषज्ञ बता देगा कि हर वर्ष सड़क पर होने वाली डेढ़ लाख मौतों में से अधिकांश की वजह होती है वाहनों की तेज रफ्तारी।केजीपी पर पलवल के समीप एक ही परिवार के सात व्यक्तियों के जान से हाथ धोने के बाद डीजीपी संधू ने गडकरी के नेशनल हाई वे अथॉरिटी को गति सीमा 120 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने को कहा जिसे गडकरी ने ठुकरा दिया।

गडकरी ने बड़ा मासूम सा तर्क दिया कि सात व्यक्तियों की मौत वाली गाड़ी चला रहे ड्राईवर को झपकी आ गयी थी और इस लिए डिवाइडर से टकरा कर उलट गयी।यदि गडकरी का यह यमराज वाला तर्क मान भी लें तो क्या डिवाइडर से टकराने वाले हर वाहन का ऐसा ही भीषण अंजाम होता है? ऐसा तभी होगा जब वाहन की रफ्तार बहुत तेज हो। अगर इस वाहन की रफ्तार भी कम होती तो शायद यमराज की जरूरत न पड़ी होती।

एक और यमराज वाला तर्क दिया गडकरी ने कि जब केजीपी एक्सप्रेस वे की सतह तेज रफ्तार के लिए बनायी गयी है तो उस पर वाहन कम रफ्तार से क्यों चलें? चलो यह तर्क मान लेते हैं। आखिर सारी दुनिया में तेज रफ्तार सतह पर तेज रफ्तार वाहन दौड़ते ही हैं। लेकिन, गडकरी बताना भूल गए, उन सड़कों पर सुरक्षा के 101 मानक भी लागू किये जाते हैं जो गडकरी के केजीपी एक्सप्रेस वे पर नदारद हैं।

दरअसल, हजारों करोड़ से बने केजीपी एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना से मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। बशर्ते सड़क, वाहन, ड्राईवर, सभी सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें गडकरी को यह सुनिश्चित करने की न तो समझ है न अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास। लिहाजा वे यमराज की आसान भूमिका ही निभाते रहेंगे।

सवाल है, अब डीजीपी संधू के पास चारा क्या है? संधू चाहें तो केजीपी एक्सप्रेस वे पर हो रही अकाल मौतों को रोक सकते हैं। ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा राज्य पुलिस का है न कि गडकरी के मंत्रालय का। संधू में दम हो तो वे स्वयं ही गति सीमा कम कर उसे लागू कर सकते हैं, इसमे किसी गडकरी की सहमति नहीं चाहिए। यहाँ तक कि केजीपी एक्सप्रेस वे पर होने वाली हर दुर्घटना के लिए गडकरी के नेशनल हाई वे अथॉरिटी के उन सम्बंधित अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सकता है जो सुरक्षा मानकों में चूक के जिम्मेदार हैं। स्वयं गडकरी भी न्याय के कठघरे में खडे किये जाने चाहिए।